यूनिट 6: भारत में शिक्षा का विकास (आज़ादी से पहले और बाद में)

नोट: सिलेबस **(UPESSC** हेडमास्टर, जूनियर हाई स्कूल — पार्ट **III):** चार्टर एक्ट (1813), ओरिएंटलिस्ट-एंग्लिसिस्ट विवाद, मैकाले का मिनट, थॉमसन के प्रयास, वुड का डिस्पैच, हंटर कमीशन, एजुकेशन पॉलिसी पर सरकारी प्रस्ताव (1913), सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, डायरकी के तहत शिक्षा, हार्टोग कमेटी, वर्धा बेसिक एजुकेशन स्कीम, सार्जेंट प्लान; गांधी। आजादी के बाद: राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, NPE 1968, NPE 1986, RTE एक्ट 2009, NEP 2020, एपीजे अब्दुल कलाम की एजुकेशनल फिलॉसफी।

चैप्टर 6.1: कंपनी रूल 1835 तक — चार्टर एक्ट 1813, ओरिएंटलिस्ट-एंग्लिसिस्ट विवाद, मैकाले का मिनट, बेंटिंक का रेज़ोल्यूशन, एडम की रिपोर्ट, थॉमसन के प्रयास

आधुनिक स्कूल प्रणाली जिसे आज उत्तर प्रदेश में एक प्रधानाध्यापक चलाता है- एक श्रेणीबद्ध स्कूल, एक सरकारी विभाग जो उसका निरीक्षण करता है, एक पाठ्य पुस्तक, एक समय सारिणी, एक परीक्षा, एक प्रशिक्षित शिक्षक जिसे वेतन मिलता है और शिक्षा के माध्यम के बारे में बहस- प्राचीन गुरुकुल या मध्ययुगीन मकतब और पाठशाला से विरासत में नहीं मिली है । इसे ब्रिटिश शासन के दौरान चरणबद्ध तरीके से बनाया गया था। उस निर्माण का पहला और सबसे रचनात्मक चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का काल **1813** से **1850** के शुरुआती

दशक का है। इन चार दशकों में राज्य ने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों को शिक्षित करना उसका कर्तव्य है (1813); क्या पढ़ाया जाए और किस भाषा में पढ़ाया जाए, इस पर तीखी बहस हुई (1813-1835); अंग्रेजी और पश्चिमी ज्ञान के पक्ष में तर्क को सुलझाया (मैकाले का मिनट और बेंटिक का संकल्प, 1835); और अंत में, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में - जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का केंद्र है - जेम्स थॉमसन ने स्थानीय भाषा वाले गाँव के स्कूलों की पहली राज्य-समर्थित प्रणाली (1843-1853) का निर्माण किया।

यह चैप्टर एग्जाम की गहराई में इन सभी माइलस्टोन को कवर करता है: बैकग्राउंड, प्रोविज़न, पर्सनैलिटी, महत्व, क्रिटिसिज़्म, और UP में एक जूनियर हाई स्कूल हेड के लिए इनसे मिलने वाले सबक।

1. बैकग्राउंड: 1813 से पहले की शिक्षा

1.1 कंपनी शासन की पूर्व संध्या पर स्वदेशी प्रणाली

जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिली (प्लासी 1757, बक्सर 1764, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765), तब भारत में पहले से ही एजुकेशन का एक बड़ा, डीसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम था:

- पाठशालाएँ - हिंदू प्रारंभिक विद्यालय, आम तौर पर एक शिक्षक (गुरु या पंडित) स्थानीय भाषा में पढ़ना, लिखना और अंकगणित (पट्टी या हिसाब-किताब सहित) पढ़ाते हैं।
- टोल / चतुष्पाठी - उच्च संस्कृत शिक्षा (व्याकरण, तर्क, कानून, दर्शन) के केंद्र, जो नदिया, मिथिला और बनारस जैसे स्थानों पर केंद्रित हैं।
- मकतब - मस्जिदों से जुड़े मुस्लिम प्राथमिक स्कूल, जो कुरान और प्रारंभिक फ़ारसी या उर्दू पढ़ाते हैं।
- मदरसे — अरबी और फ़ारसी में हाई इस्लामिक शिक्षा के सेंटर थे; फ़ारसी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी।

इन संस्थाओं को शासकों, ज़मींदारों, मंदिर और मस्जिद के दान और

माता-पिता की फीस (अक्सर चीज़ों के रूप में) से मदद मिलती थी। इन्हें किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने नहीं चलाया था, इनकी कोई छपी हुई किताबें नहीं थीं, कोई तय टाइमटेबल नहीं था, और कोई फॉर्मल परीक्षाएँ नहीं थीं। अठारहवीं सदी की राजनीतिक उथल-पुथल और पुराने ग्राहकों के चले जाने से ये कमज़ोर हो गईं, लेकिन इनकी संख्या बनी रही — यह बात विलियम एडम ने 1830 के दशक में लिखी थी।

1.2 कंपनी का शुरुआती रवैया: तटस्थता और उदासीनता

कंपनी एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन थी। इसके डायरेक्टरों को डर था कि भारतीयों के धर्म और पढ़ाई में दखल देने से अशांति फैलेगी और व्यापार को नुकसान होगा। इसलिए इसकी शुरुआती पॉलिसी धार्मिक रूप से तटस्थ रहना और पढ़ाई-लिखाई में कोई दिलचस्पी न रखना थी। इसने मिशनरियों का भी विरोध किया: 1813 से पहले मिशनरी कंपनी के इलाके में आसानी से नहीं आ सकते थे, इसीलिए बैपटिस्ट मिशनरी विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड ने सेरामपुर की डेनिश बस्ती (सेरामपुर मिशन, 1800) से काम किया, जहाँ उन्होंने स्कूल, एक प्रिंटिंग प्रेस और बाइबिल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद शुरू किया।

1.3 अलग-अलग शुरुआती कोशिशें (1813 से पहले)

हालांकि कोई पॉलिसी नहीं थी, फिर भी कुछ अधिकारियों ने संस्थाएं बनाईं, खासकर कंपनी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने या पढ़े-लिखे लोगों की अच्छी नीयत जीतने के लिए:

वर्ष	संस्था	संस्थापक	उद्देश्य
1781	कलकत्ता मदरसा	वॉरेन हेस्टिंग्स	अरबी और फ़ारसी सीखना; मुस्लिम लॉ ऑफ़िसर तैयार करना

वर्ष	संस्था	संस्थापक	उद्देश्य
1784	एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल	सर विलियम जोन्स	ओरिएंटल रिसर्च (टीचिंग बॉडी नहीं)
1791	संस्कृत कॉलेज, बनारस	जोनाथन डंकन (बनारस निवासी)	हिंदू कानून और संस्कृत शिक्षा
1800	फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता	लॉर्ड वेलेस्ली	युवा ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना
1800	सेरामपुर मिशन	कैरी, मार्शमैन, वार्ड	स्थानीय स्कूल, प्रिंटिंग, बाइबल का अनुवाद

खास बातें: दो सबसे शुरुआती "ओरिएंटलिस्ट" इंस्टीट्यूशन कलकत्ता मदरसा **(1781,** वॉरेन हेस्टिंग्स) और बनारस संस्कृत कॉलेज **(1791,** जोनाथन डंकन) हैं। बनारस कॉलेज आज के उत्तर प्रदेश में है; यह आज के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ।

1.4 बदलाव के लिए दबाव: चार्ल्स ग्रांट और इवेंजेलिकल्स

ब्रिटेन में, इवेंजेलिकल मूवमेंट का तर्क था कि ब्रिटेन की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह ईसाई धर्म और पश्चिमी ज्ञान के ज़रिए भारतीयों को "बेहतर" बनाए। चार्ल्स ग्रांट , जो कंपनी के एक अधिकारी और बाद में डायरेक्टर बने, ने ' ऑब्ज़र्वेशन्स ऑन द स्टेट ऑफ़ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन' (1792 में लिखी गई) लिखी, जिसमें तर्क दिया गया कि इंग्लिश शिक्षा और ईसाई शिक्षा ही भारतीय

समाज की नैतिक गिरावट का इलाज है। उनके सहयोगी विलियम विल्बरफ़ोर्स ने पार्लियामेंट में इस मामले पर ज़ोर दिया। उनकी कोशिश 1793 के चार्टर रिन्यूअल में नाकाम रही लेकिन 1813 में सफल हुई। इसलिए ग्रांट को अक्सर एंग्लिसिस्ट सोच और मिशनरी शिक्षा का आगे बढ़ाने वाला बताया जाता है।

2. 1813 का चार्टर अधिनियम

2.1 चार्टर एक्ट क्या था

भारत में कंपनी के अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के दिए गए चार्टर के तहत थे और हर बीस साल (1793, 1813, 1833, 1853) में रिन्यू किए जाते थे। हर रिन्यूअल पार्लियामेंट के लिए भारतीय मामलों का रिव्यू करने का एक मौका बन गया। 1813 के एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट **1813** के नाम से भी जाना जाता है।

2.2 मुख्य प्रावधान (सामान्य)

- भारत के साथ व्यापार पर कंपनी की मोनोपॉली खत्म कर दी गई (चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर मोनोपॉली बरकरार रखी गई)।
- कंपनी के भारतीय इलाकों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया।
- मिशनरियों (और लाइसेंस के तहत दूसरे ब्रिटिश लोगों) को भारत में आने और प्रचार करने की इजाज़त दी गई।
- इसमें प्रसिद्ध शिक्षा खंड - धारा **43** शामिल था।

2.3 शिक्षा खंड (धारा 43)

इस एक्ट ने गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को अधिकार दिया कि वह सरप्लस इलाके के रेवेन्यू में से "हर साल कम से कम एक लाख रुपये" अलग रखे, जिसका इस्तेमाल "साहित्य को फिर से शुरू करने और बेहतर बनाने, भारत के पढ़े-लिखे लोगों को बढ़ावा देने, और भारत में ब्रिटिश इलाकों के लोगों में विज्ञान की जानकारी को शुरू करने और

बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।"

इस क्लॉज़ के तीन वाक्यों ने अगले बीस सालों का विवाद खड़ा कर दिया:

1. "साहित्य का पुनरुत्थान और सुधार" — कौन सा साहित्य? संस्कृत और अरबी, या अंग्रेजी?
2. "पढ़े-लिखे मूल निवासियों को बढ़ावा देना" — पारंपरिक सिस्टम के पंडित और मौलवी?
3. "विज्ञान के ज्ञान का परिचय और प्रचार" — पश्चिमी विज्ञान, जिसे केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता था (यह तर्क दिया गया था)?

2.4 महत्व

- **राज्य की ज़िम्मेदारी को पहली बार मानना** : शिक्षा पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक खर्च का मामला बन गई। जेपी नाइक ने इसे शिक्षा के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी की ओर पहला कानूनी कदम बताया।
- मिशनरी शिक्षा को कानूनी मान्यता मिली; 1813 के बाद मिशनरी स्कूल तेज़ी से फैले।
- ओरिएंटलिस्ट-एंग्लिसिस्ट विवाद का बीज बोया क्योंकि यह क्लॉज़ कंटेंट और मीडियम के बारे में साफ़ नहीं था।

2.5 सीमाएं और आलोचना

- यह रकम एक सबकॉन्टिनेंट के लिए बहुत कम थी; इसके अलावा, इसे असल में लगभग दस साल (1823 तक) तक खर्च नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी ने यह तय नहीं किया था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए।
- इस एक्ट में आम लोगों या शुरुआती शिक्षा के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था; इसका मकसद "पढ़े-लिखे मूल निवासी" थे।
- ग्रांट को मैनेज करने के लिए कोई मशीनरी नहीं थी।

एग्जामिनर का जाल: 1813 का ₹1 लाख इंग्लिश एजुकेशन के लिए ग्रांट नहीं था। यह "लिटरेचर को फिर से शुरू करने और बेहतर बनाने", "पढ़े-लिखे लोगों" और "साइंस" के लिए था — ये वो शब्द थे जिन्हें ओरिएंटलिस्ट क्लासिकल लर्निंग के सपोर्ट के तौर पर पढ़ते थे। इंग्लिश को **1835** में ही चुना गया था।

एग्ज़ाम पॉइंट: मैच: चार्टर एक्ट **1813** → ₹1 लाख हर साल + मिशनरियों को इजाज़त + भारत के साथ ट्रेड मोनोपॉली का खत्म होना। चार्टर एक्ट **1833** → बंगाल के गवर्नर-जनरल भारत के गवर्नर-जनरल बने (बेंटिंक पहले); मैकाले पहले लॉ मेंबर के तौर पर भारत आए। चार्टर एक्ट **1853** → आखिरी रिन्यूअल; वुड्स डिस्पैच 1854 से पहले।

2.6 1833 का चार्टर एक्ट और शिक्षा

1833 का एक्ट (सेंट हेलेना एक्ट) कोई एजुकेशन एक्ट नहीं है, लेकिन यह इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसने गवर्नर-जनरल की काउंसिल के लॉ मेंबर का पद बनाया, जिससे थॉमस बैबिंगटन मैकाले 1834 में भारत आए। इसने कंपनी के कमर्शियल काम भी पूरी तरह खत्म कर दिए और यूरोपियन लोगों को ज़्यादा आज़ादी से आने की इजाज़त दी, जिससे इंग्लिश की मांग बढ़ी।

3. सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति (1823)

दस साल तक ₹1 लाख ज़्यादातर बिना खर्च हुए पड़े रहे। **1823** में बंगाल सरकार (गवर्नर-जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के अंडर) ने एजुकेशनल ग्रांट को मैनेज करने के लिए कलकत्ता में जनरल कमिटी ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन **(GCPI)** बनाई। इसके मुख्य सदस्य ओरिएंटलिस्ट थे, खासकर **HT** प्रिंसेप और होरेस हेमैन विल्सन। उनके असर में कमिटी ने:

- कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज को फिर से बनाया

गया।

- संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता **(1824)** की स्थापना की और आगरा (1823) में ओरिएंटल कॉलेज को सपोर्ट किया।
- संस्कृत और अरबी किताबें छापने (जिनमें से कई बिक नहीं पाईं) और क्लासिकल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को वजीफे देने पर बहुत खर्च किया गया।
- इंग्लिश क्लास को सिर्फ़ कुछ हद तक ही सपोर्ट किया गया।

इस तरह कमिटी ने 1813 के क्लॉज़ की ओरिएंटलिस्ट रीडिंग को फॉलो किया। 1830 के दशक की शुरुआत में जब एंग्लिसिस्ट विचारों वाले युवा सदस्य (चार्ल्स ट्रेवेलियन उनमें से एक थे) शामिल हुए, तो कमिटी दो बराबर ग्रुप में बंट गई — पांच बनाम पांच — और पॉलिसी तय नहीं कर सकी। रुकावट सरकार को सौंप दी गई, और इसी तरह मैकाले की कहानी में एंट्री हुई।

खास बातें: हिंदू कॉलेज, कलकत्ता **(1817)** की स्थापना भारतीयों की पहल — डेविड हेयर, राजा राममोहन रॉय के ग्रुप और कलकत्ता के नागरिकों, जस्टिस सर एडवर्ड हाइड ईस्ट के साथ — ने इंग्लिश और वेस्टर्न पढ़ाई के लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर की थी। इससे पता चलता है कि 1835 से बहुत पहले से ही भारतीयों में इंग्लिश की मांग थी। बाद में यह प्रेसीडेंसी कॉलेज बन गया।

UP फोकस: आज के उत्तर प्रदेश के दो सबसे पुराने मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन इसी समय के हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज **(1791)** संस्कृत सीखने को बढ़ावा देने के लिए कंपनी का सबसे पहला काम था, और आगरा कॉलेज **(1823)** , जो पंडित गंगाधर शास्त्री के एंडोमेंट से बना था, एक ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर शुरू हुआ और बाद में इसमें इंग्लिश क्लास भी जोड़ी गईं। उनका इतिहास पूरे विवाद को दिखाता है: दोनों ओरिएंटलिस्ट इंस्टिट्यूशन के तौर पर शुरू हुए और 1835 के बाद इंग्लिश और वेस्टर्न सब्जेक्ट की ओर बढ़े। UP कैंडिडेट के लिए, ये इंस्टिट्यूशन तब काम के उदाहरण हैं जब कोई सवाल ओरिएंटलिस्ट-एंग्लिसिस्ट बहस के रीजनल असर के बारे में पूछता है।

4. ओरिएंटलिस्ट-एंग्लिसिस्ट विवाद (1813-1835)

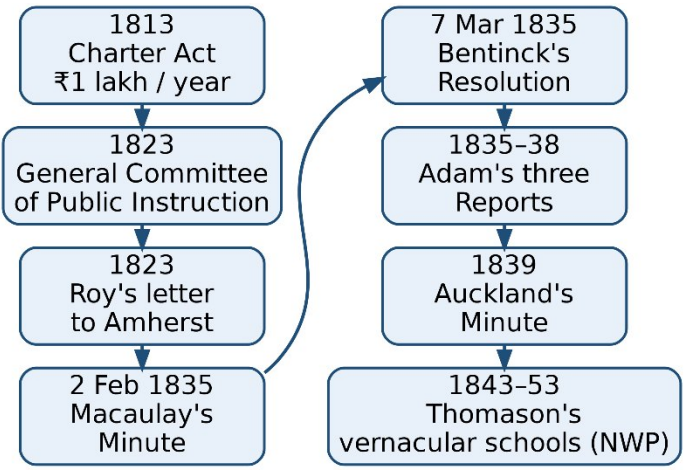

चित्र 6.1.1: शिक्षा में कंपनी-काल के मील के पत्थर, 1813–1853

4.1 विवादित प्रश्न

विवाद तीन जुड़े हुए सवालों के बारे में था:

1. विषय-वस्तु - क्या सरकारी कोष से पारंपरिक भारतीय शिक्षा (संस्कृत, अरबी, फ़ारसी साहित्य, हिंदू और इस्लामी कानून और दर्शन) को बढ़ावा मिलना चाहिए या पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को?
2. माध्यम - क्या शिक्षा शास्त्रीय भाषाओं में, अंग्रेज़ी में या स्थानीय

भाषाओं (मातृभाषाओं) में होनी चाहिए?

3. लक्ष्य — क्या राज्य को शिक्षित वर्गों और अभिजात वर्ग (जो फिर बाकी लोगों को प्रभावित करेंगे) को शिक्षित करना चाहिए, या सीधे आम जनता को?

4.2 ओरिएंटलिस्ट (क्लासिकिस्ट)

प्रमुख हस्तियां: सर विलियम जोन्स (पहले, बौद्धिक संस्थापक), एचटी कोलब्रुक , एचएच विल्सन , एचटी प्रिंसेप , और GCPI के ओरिएंटलिस्ट सदस्य।

तर्क:

- 1813 के क्लॉज़ में लिटरेचर को "फिर से शुरू करने" और "पढ़े-लिखे लोगों" को बढ़ावा देने की बात कही गई थी; कानून खुद क्लासिकल पढ़ाई का पक्ष लेता था।
- भारतीय अपनी क्लासिकल शिक्षा का सम्मान करते थे; इसका समर्थन करने से प्रभावशाली वर्गों की अच्छी भावना मिलेगी और कंपनी राजनीतिक रूप से सुरक्षित रहेगी।
- फिलॉसफी, कानून, साहित्य और गणित में भारत की विरासत को बचाए रखने की ज़रूरत है।
- पश्चिमी ज्ञान को संस्कृत और अरबी में अनुवाद के ज़रिए धीरे-धीरे पेश किया जा सकता था।

कमज़ोरियाँ: इसने एक छोटे से ब्राह्मण और अशरफ़ अमीर लोगों की सेवा की; इसने पुरानी किताबों की तरफ़ देखा; इसकी छपी हुई किताबें नहीं बिकीं; और इसने आम लोगों को नज़रअंदाज़ किया।

4.3 एंग्लिसिस्ट

प्रमुख हस्तियाँ: टीबी मैकाले , चार्ल्स ट्रेवेलियन , स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ (जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन के संस्थापक, कलकत्ता, 1830), और - भारतीयों में - राजा राममोहन राय । चार्ल्स ग्रांट को शुरुआती अग्रदूत माना जाता है।